उदयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट:
न सीएनजी-न ईवी, धुआं छोड़ते दौड़ रहे डीज़ल टैंपों

राजस्थान के अलग-अलग शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर लगातार काम हो रहा है, लेकिन इनके मुकाबले उदयपुर काफी पीछे नजर आ रहा है। अलवर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, अजमेर जैसे बड़े शहर करीब एक दशक पहले ही डीज़ल टेम्पो (विक्रम टेम्पो) को विदा कर चुके हैं और उन की जगह ई-रिक्शा, अतिरिक्त सिटी बस या सीएनजी ऑटो जैसी गाड़ियों ने ले ली है, लेकिन अब भी लेकसिटी उदयपुर में डीज़ल टैंपों धुआं छोड़ते हर इलाके में नजर आ जाएंगे। ये स्थिति भी तब है, जबकि ये शहर पर्यटकों का शहर है और स्मार्ट सिटी भी। आम जनता को भी मजबूरी में इनमें सफर करना पड़ता है। सूरजपोल, उदियापोल, ठोकर, अस्पताल, टाउनहॉल, सेवाश्रम जैसे चौराहों पर सिटी बसों की जगह लाइन से कंडम टैंपों खड़े नजर आएंगे। देश की बात करें तो पुणे, भोपाल, इंदौर, आगरा, देहरादून, लखनऊ, इलाहाबाद समेत कई अन्य छोटे शहरों में सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं।

दूसरी ओर, उदयपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कंडम डीज़ल टैंपों पर टिकी हुई है। उदयपुर स्मार्ट सिटी निर्देशों के तहत भी इन तीन पहिया वाहनों को असुरक्षित, असहज और अत्यधिक प्रदूषण कारक वाहन के रूप में माना गया था। इसके बावजूद शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्हीं की बड़ी भूमिका है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ही अलवर शहर में २०१३ में ऐसे टैंपों बंद कर दिए गए थे। इस पहल को कई शहरों में मॉडल की तरह अपनाया गया था। जयपुर में ई-रिक्शा, लो फ्लोर बसें और मेट्रो रेल चल रहे हैं। कोटा और जोधपुर में भी करीब ७-८ साल पहले ऐसे टैंपों बंद कर दिए गए।

सीएनजी की तुलना में ५० से ६० फीसदी अधिक प्रदूषण करते हैं डीज़ल वाहन

ईपीसीए (एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी) की रिपोर्ट के मुताबिक तिपहिया डीज़ल वाहन पेट्रोल और सीएनजी वाहनों की तुलना में ५० से ६० प्रतिशत अधिक प्रदूषण करते हैं। अगर बीएस-सिक्स डीज़ल कार से भी इनकी तुलना करें तो लगभग ६ गुना अधिक प्रदूषक तत्व छोड़ते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी शहर में अगर डीज़ल विक्रम टैंपों चल रहे हैं तो वहां के प्रदूषण का ४०-५० फीसदी हिस्सा इसी का है।

उदयपुर शहर में पिछले साल ०६ महीने १०० से अधिक रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) स्तर			
एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) स्तर	**२०२१**	**२०२२**	**२०२३**
०-५०	०० माह	०० माह	०० माह
५१-१००	०६ माह	०३ माह	०६ माह
१०१-१५०	०३ माह	०४ माह	०३ माह
१५१-२००	०३ माह	०३ माह	०३ माह
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के आंकड़े			

पर्यावरण मंत्रालय के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम प्रोजेक्ट में शामिल शहरों की सूची में उदयपुर भी है। इसकी गाइडलाइन के मुताबिक भी शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीज़ल इंजन फ्री करना है। इनसे धुआं काफी मात्रा में निकलता है। स्मोक डेंसिटी बढ़ती है। शहर की वायु गुणवत्ता के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अहम रोल होता है।

उदयपुर में १० लाख से ज्यादा वाहन, लेकिन इलेक्ट्रिक महज ५८२३

जिला परिवहन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक उदयपुर में कुल १०,०६,५१९ वाहन हैं। इनमें से महज ५८२३ (०.५७ प्रतिशत) वाहन ही इलेक्ट्रिक हैं। जबकि केंद्र और राज्य सरकार साल २०३० तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या ३० प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी हैं। इसे बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग श्रेणी में प्रोत्साहन राशि भी मुहैया करा रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर शहर में सिर्फ २४ सिटी बसें हैं। ये सभी डीज़ल की हैं। इनमें हर रोज ८ से १० हजार लोग सफर करते हैं। शहर में ३५ नई सीएनजी बसें प्रस्तावित हैं, लेकिन सीएनजी वाहन अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसके अलावा एक भी इलेक्ट्रिक वाहन सरकारी स्तर पर नहीं चल रहा।

हर साल फिटनेस जांच ज़रूरी; किन्तु होती नहीं

जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार डीज़ल सवारी वाहनों को शुरूआती ०८ साल में साल में दो बार जबकि उसके बाद हर साल फिटनेस प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। किन्तु कार्यालय स्वयं स्वीकार करता है कि ऐसा होता नहीं है। इस स्थिति में फिटनेस प्रमाण पत्र के अभाव में बहुत हद तक संभव है कि ये टेम्पो अधिक धुआं छोड़ते हो ! कार्यालय के अनुसार डीज़ल टेम्पो की फिटनेस जांच में सही व्यवस्था का अभाव झलकता है। वे इस पर कार्रवाही का भरोसा ज़रूर देते हैं।

उदयपुर में यह भी देखा गया है कि एक ही व्यक्ति के पास ५ या उस से से अधिक टेम्पो है, जिसे वह प्रतिदिन किराए पर चलाने को अन्य लोगों को देते हैं। अधिक कमाई के चक्कर में ये लोग क्षमता से अधिक सवारियां भरते हैं; ऐसे में हादसों का डर तो बना रहता है ही; साथ ही में ज्यादा लोड होने से ये अधिक धुआं छोड़ते हैं।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अनुसार किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अनुपात में डीज़ल टेम्पो उत्सर्जन, रखरखाव, परिचालन लागत, सुरक्षा, सार्वजानिक स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव में काफी नकारात्मक असर डालते हैं।

कारक	इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा	पारंपरिक ऑटो-रिक्शा
उत्सर्जन	शून्य टेलपाइप उत्सर्जन	टेलपाइप उत्सर्जन का उच्च स्तर
ध्वनि प्रदूषण	कम ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं	उच्च स्तर का ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं
सार्वजनिक स्वास्थ्य	वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है और श्वसन संबंधी बीमारियाँ कम होती हैं	वायु प्रदूषण और श्वसन संबंधी बीमारियों में योगदान देता है
आर्थिक प्रभाव	संचालन लागत कम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियाँ पैदा करता है और ईंधन आयात कम करता है	संचालन/परिवहन लागत ज्यादा उच्च ईंधन लागत और कम दक्षता के कारण सीमित आर्थिक लाभ

चलते चलते,

नगर निगम द्वारा जब २४ सिटी बसें लायी गयी, तो यह सोचा गया था कि इस से स्वतः ही धीरे धीरे डीज़ल टेम्पो कम हो जायेंगे। सिटी बस में ५ किमी तक के सफ़र का ५ से १० रूपया टिकट दर है, जबकि डीज़ल टेम्पो में यही दर २० से ५० रुपये तक है। किन्तु परिवहन विभाग के अनुसार २०२२ के मुकाबले २०२३ में डीज़ल टेम्पो की दर १८% से बढ़ी है। ऐसे में बहुत हद तक यह आवश्यक है कि निगम शहर में स्वच्छ ईंधन सार्वजनिक वाहन प्रणाली को बढ़ावा दे और तथा राज्य सरकार से इलेक्ट्रिक बसों के लिए ज्यादा संजीदगी से पैरवी करे।

निगम को सोचना होगा कि यह शहर केवल यहाँ के निवासियों का शहर नहीं है, ये शहर पर्यटकों का भी शहर है। यहाँ के निवासियों के साथ साथ यहाँ आने वाला पर्यटक भी साफ़ हवा में सांस ले सके और अच्छी यादें यहाँ से लेकर जाए ।

दोनों फोटो साभार- प्रदीप सोनी, उदयपुर